ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.20, No.3, July-Sept., 2025/30

औद्योगिक उपक्रमों का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव

अवधेश मौर्या एवं सुधांशु वर्मा
https://doi.org/ 10.61410/had.v20i3.248

शोध–सार

भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 1991 के आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् औद्योगिक विकास तीव्र गति से बढ़ा, उद्योगों का विस्तार नगरीय क्षेत्र तक सीमित न होकर ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। वास्तव में ग्रामीण सामाजिक संरचना को औद्योगिक गतिविधियों ने बड़ी गहराई तक प्रभावित किया है। ग्रामीण जीवन पर औद्योगिक उपक्रमों का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रही है। जहाँ ग्रामीण परिवेश में भी रोजगार, आय और तकनीकी उद्योग का प्रचलन बढ़ा है, वहीं औद्योगिक इकाईयों से वायु, जल और भूमि प्रदूषण का प्रभाव बढ़ा है। खाद्य सुरक्षा पर भी संकट आया। औद्योगिक अधिग्रहण से कहीं न कहीं किसानों में भूमिहीनता भी बढ़ी, सिंचाई के स्रोत प्रभावित हुए। साथ ही ग्रामीण समाज में आधुनिकता, शिक्षा रोजगार के साथ विकास कार्य हो रहा है।

शब्द संकेत – आर्थिक उदारीकरण, अधिग्रहण, सामाजिक संरचना, संयन्त्र कुटीर उद्योग, औद्योगिक, इस्पात, कार्यविधि, उपक्रम, सामुदायिक विकास

शोध–पत्र

औद्योगिक उपक्रमों का आशय उन संगठनों से है जो उत्पादन, वितरण अथवा सेवा के क्षेत्र में मशीन, तकनीकि एवं पूँजीनिवेश के माध्यम से कार्य किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना है, साथ ही वह सामाजिक संरचना एवं पर्यावरण पर भी अपनी गहरा प्रभाव डालते हैं। देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 से लेकर 1962 तक बेहतर तरीके से चलता रहा। जिसमें कृषि के अतिरिक्त पशु–पालन, समाज–शिक्षा, सहकारित, पंचायत एवं सड़कों इत्यादि के निर्माण पर विशेष बदल दिया गया। परन्तु गृह उद्योगों एवं ग्रामोद्योग पर विशेष ध्यान नहीं दिया।[1] ग्रामीण परिवेश में लघु एवं कुटीर उद्योग की संकल्पना महात्मा गाँधी ने की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के किसान, नवयुवक अतिरिक्त समय में लघु उद्योगों के माध्यम से अपनी जीविका चला सकें। वहीं बड़े–बड़े उद्योगों यथा–इस्पात संयन्त्र, सीमेन्ट फैक्ट्री, खनन उद्योग, रासायनिक उद्योग इत्यादि।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगीकरण को विस्तार दिया भारी उद्योग, इस्पात संयन्त्र (भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला) कोयला और लौह खदान, सीमेन्ट फैक्ट्री चीनी मिलें इत्यादि को ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्र में स्थापित किया गया। कृषि क्षेत्र के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों यथा वृहत एवं मध्यम उद्योग, लघु तथा कुटीर उद्योग, खादी तथा ग्रामीण उद्योग, हस्त शिल्प, हथकरधा इत्यादि के विकास हेतु सरकारी संगठनों जिसमें राज्य स्तर पर उद्योग निदेशालय तथा जनपद स्तर

- **शोध छात्र–समाजशास्त्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)**
- **शोध निर्देशक–असि0 प्रोफेसर, समाजशास्त्र आचार्य देव किसान पी0जी0 कालेज, बभनान, गोण्डा (उ0प्र0)**

पर जिला उद्योग केन्द्र का सशक्त ढाँचा विद्यमान है। इसका मुख्य कार्य नवीन उद्योगों को आकर्षित करना तथा पुराने उद्योगों को पुनः स्थापित करना था। राज्य सरकार के अथक प्रयासों से इसकी प्राकृतिक अनुकूलता के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश विभिन्न स्थानों पर स्थापित औद्योगिक संस्थानों के आस–पास अनेकों औद्यौगिक इकाइयों को आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की।[2]

उद्योगों की सफलतापूर्वक तभी सम्भव हो सकता है, जब मशीनें यन्त्र हों, इसका परिणाम यह होता है कि उद्योगों में यन्त्रों और मशीनों को स्वीकार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। इसी प्रक्रिया को यन्त्रीकरण भी कहा जाता है। औद्योगीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यन्त्र ही उद्योगों का आधार होता है। छोटे उद्योगों को विशाल उद्योगों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। मशीनों ने उद्योगों को क्रान्तिकारी परिवर्तनों की ओर अग्रसर किया है।[3] समाज में औद्योगीकरण के कारण परिवार की संरचना में भी परिवर्तन सम्भव है जो उस समाज की कार्यविधि के लिए उपयुक्त प्रमाणित होता है। औद्योगिक दृष्टि से परिवार के कुछ विशिष्ट प्रकार अन्य प्रकारों की तुलना में औद्योगीकरण में अधिक सहायक होंगे।[4]

1991 के उदारीकरण के पश्चात् बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और निजी क्षेत्र की भागीदारी ने इस प्रक्रिया को और गतिमान किया है, इसके परिणाम स्वरूप गाँव मात्र कृषि केन्द्रित न होकर औद्योगिक सम्पर्क केन्द्र भी बन गये हैं। औद्योगीकरण के प्रभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में भी नये रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए है, कृषि पर निर्भरता घटकर लोग औद्योगिक मजदूरी, परिवहन और सेवा क्षेत्र से जुड़कर आय और उपभोग का स्तर भी बढ़ा है। औद्योगिक सुधारों के सकारात्मक प्रभाव तथा सम्बन्धित लाभों जो राष्ट्रीय स्तर पर असाधारण व व्यापक थे, उसका प्रयोग कतिपय अन्तर्निहित बाध्यताओं के कारण उत्तर प्रदेश को गतिशील बनाने में नहीं किया जा सकता हैं।[5]

शोध प्रारूप

प्रस्तुत शोध अध्ययन अयोध्या जनपद के मसौधा विकास खण्ड में सम्मिलित औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत कुल 300 श्रमिकों का उद्देश्य पूर्ण निदर्शन पद्धति के आधार पर चयन किया गया है। इस अध्ययन को सर्वोत्तम बनाने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों की सहायता से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है।

अध्ययन की परिकल्पना –

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्माण किया गया है –

1. औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों के सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. औद्योगिक उपक्रमों कार्य की प्रकृति एवं कार्य दशाओं पर प्रकाश डालना।
3. नियोक्ता वर्ग एवं श्रमिकों के बीच सम्बन्धों की प्रकृति एवं समन्वय का विश्लेषण करना।
4. श्रमिकों के कार्य के प्रति सन्तुष्टि एवं असन्तुष्टि का पता लगाना।
5. कार्यस्थल पर श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाना।
6. औद्योगिक उपक्रमों का ग्रामीण जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालना।

अध्ययन की उपकल्पना

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उपकल्पनाओं पर आधारित है :–

1. किसी भी औद्योगिक उपक्रम में नियोक्त व श्रमिकों के बीच जितना बेहतर समन्वय होगा उतना ही अधिक औद्योगिक लाभ की सम्भावना होगी।
2. औद्योगिक उपक्रम श्रमिकों के कल्याण हेतु जितना अधिक पारदर्शी होगा ग्रामीण जीवन पर भी उसका प्रभाव उतना अधिक होगा।
3. कार्यस्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं की कम उपलब्धता औद्योगिक विवाद को जन्म देती है।
4. वेतन, मौद्रिक लाभ अथवा आर्थिक प्रोत्साहन श्रमिकों की कार्य संतुष्टि का एक कारक हो सकता है, निर्णायक नहीं, क्योंकि श्रमिक केवल आर्थिक मानव नहीं होता, वह एक सामाजिक मानव भी है।
5. किसी भी स्थान पर लगे औद्योगिक उपक्रम स्थानीय विकास को भी प्रभावित करता है।
6. औद्योगिक उपक्रमों में श्रमिकों की गतिशीलता का उनकी आर्थिक स्थिति के साथ महत्वपूर्ण सम्बन्ध है।

उपर्युक्त सन्दर्भों के साथ औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को देखने का प्रयास किया गया है कि ''क्या औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति उच्च हुई है'' ? निम्नलिखित सारणी के द्वारा उत्तरदाताओं का विचान जानने का प्रयास किया गया है।

सारणी सं0–1.0

क्रम सं0	समाजिक–आर्थिक विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1-	हाँ	180	60.00
2-	नही	65	21.67
3-	कह नहीं सकते	55	18.33
	योग	**300**	**100.00**

उपरोक्त सारणी सं0–1.0 के अध्ययन में सम्मिलित औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि ''क्या आपकी सामाजिक–आर्थिक औद्योगिक उपक्रमों में कार्य करने से उच्च हुई है।'' ? के क्रम में सम्पूर्ण 300 उत्तरदाताओं में से कुल 100 (60.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि हाँ औद्योगिक उपक्रमों में कार्य करने से उनकी आर्थिक स्थिति अवश्य उच्च हुई है। जबकि कुल 65 (21.67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते है कि उनके औद्योगिक उपक्रमों में कार्य करने से प्रस्थिति अच्छी हुई, एवं 55 (18.33 प्रतिशत) उत्तरदाता इस प्रश्न के सन्दर्भ में कुछ नहीं कर सके।

अतः सम्पूर्ण अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक उपक्रमों में कार्यशील श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति अवश्य अच्छी हुई है।

सारणी सं0–2.0

औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति पारिवारिक दृष्टिकोण ?

क्रम सं0	समाजिक जीवन के प्रति विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1-	अच्छा	235	78.33
2-	खराब	42	14.00
3-	बहुत खराब	23	7.67
	योग	**300**	**100.00**

उपरोक्त सारणी सं0–2.0 के अध्ययन में सम्मिलित औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि ''कार्यरत श्रमिकों के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति पारिवारिक दृष्टिकोण कैसा है के क्रम में सम्पूर्ण 300 उत्तरदाताओं में से कुल 235 (78.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना है कि औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को पारिवारिक सदस्यों ने बहुत अच्छा माना है, जबकि कुल 425 (14.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कथन है कि औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव बहुत खराब है ? एवं मात्र 23 (7.67 प्रतिशत) उत्तरदाता इस प्रश्न के सन्दर्भ में कुछ नहीं कर सके।

अतः सम्पूर्ण अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों का सामाजिक जीवन बहुत अच्छा है उनके परिवार का भी यही मानना है कि वास्तव में औद्योगिक उपक्रमों का ग्रामीण जीवन में बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है।

संदर्भ–सूची :

1. सिंह, बैजनाथ ; सामुदायिक ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय पुस्तक न्याय भारत नई दिल्ली, पृ0–97
2. झाँ सुबोधनाथ; उत्तर प्रदेश : देश और लोग, राष्ट्रीय पुस्तक न्याय भारत नई दिल्ली, पृ0–145
3. बघेल, डी0एस0 ; औद्योगिक समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली पृ0–43
4. शर्मा, के0एल0 ; भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ0–131
5. झाँ सुबोधनाथ; उत्तर प्रदेश : देश और लोग, राष्ट्रीय पुस्तक न्याय भारत नई दिल्ली, पृ0–146